भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 55 का उत्तर

रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई रेललाइन

***55. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई रेललाइनें बिछा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में उक्त नई रेललाइनों के निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 03.12.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 55 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): मध्य प्रदेश में रतलाम के निकट संपर्कता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

क्रम सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रूपए में)	लंबाई (किलोमीटर में)	पूरा किया गया	टिप्पणी
1.	दाहोद-इंदौर नई लाइन	9746	205 कि.मी.	57 कि.मी.	शेष कार्य प्रगति पर है।
2.	नीमच-रतलाम दोहरीकरण	1,096	133 कि.मी.	93 कि.मी.	शेष कार्य प्रगति पर है।
3.	छोटा उदयपुर-धार नई लाइन	1,794	157 कि.मी.	72 कि.मी.	शेष कार्य प्रगति पर है।
4.	रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन	964	41 कि.मी.	भूमि अधिग्रहण के अधीन	हाल ही में स्वीकृत
5.	वड़ोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन	8,387	259 कि.मी.	भूमि अधिग्रहण के अधीन	हाल ही में स्वीकृत
6.	रतलाम-खंडवा आमान परिवर्तन	7,265	299 कि.मी.	212 कि.मी.	शेष कार्य प्रगति पर है।

<u>मध्य प्रदेश</u>

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल परियोजनाएँ भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं।

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	632 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2025-26	14,745 करोड़ रुपए (23 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-25 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ की लंबाई	कमीशन किए गए नए रेलपथ की औसत लंबाई
2009-14	145 किलोमीटर	29 किलोमीटर प्रति वर्ष
2014-25	2,651 किलोमीटर	241 किलोमीटर प्रति वर्ष (8 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 89,543 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 4,740 किलोमीटर लंबाई की 24 रेल परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से मार्च, 2025 तक 2092 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 41,401 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है: -

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	8	1914	544	15069
आमान परिवर्तन	2	809	430	6766
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	14	2017	1118	19566
कुल	24	4,740	2,092	41,401

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी हुई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	गुना-इटावा नई लाइन (348 किलोमीटर)	683
2.	जबलपुर-गोंदिया आमान परिवर्तन (300 किलोमीटर)	2005
3.	छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन (150 किलोमीटर)	1512
4.	छिंदवाड़ा-मंडला फोर्ट आमान परिवर्तन (182 किलोमीटर)	1268
5.	घाट पिंडारी-बलखेड़ा दोहरीकरण (6 किलोमीटर)	29
6.	गुना-रुठियाई दोहरीकरण (20 किलोमीटर)	175
7.	खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (62 किलोमीटर)	489
8.	झुकेही कॉर्ड लाइन, कटनी यार्ड को बाईपास करते हुए (2 किलोमीटर)	12
9.	सोनतलाई-बागरातवा दोहरीकरण (7 किलोमीटर)	110
10.	इटारसी-बुधनी तीसरी लाइन (25 किलोमीटर)	286
11.	तीगांव-चिचोंडा घाट खंड तीसरी लाइन (17 किलोमीटर)	176
12.	भोपाल-बीना तीसरी लाइन (145 किलोमीटर)	1075
13.	बरखेड़ा-भोपाल तीसरी लाइन (41 किलोमीटर)	473
14.	नागदा-उज्जैन गंभीर पुल का दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	28
15.	पेंड्रा रोड-अनुपपुर तीसरी लाइन (50 किलोमीटर)	394
16.	बीना-कोटा दोहरीकरण (283 किलोमीटर)	2477
17.	नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण (56 किलोमीटर)	560

18.	बिलासपुर में फ्लाईओवर के साथ खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (72 किलोमीटर)	792
19.	बुदनी-बरखेड़ा तीसरी लाइन (27 किलोमीटर)	1703
20.	इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण (79 किलोमीटर)	757
21.	अप दिशा में पोवारखेड़ा-जुझारपुर एकल लाइन फ्लाईओवर (16 किलोमीटर)	443
22.	अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन (165 किलोमीटर)	2311
23.	रमना-सिंगरौली दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	2436
24.	करैला रोड-शक्तिनगर दोहरीकरण (32 किलोमीटर)	763
25.	मालखेड़ी-महादेवखेड़ी दोहरीकरण (12 किलोमीटर)	59

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा शुरू की गई कुछ परियोजनाएं, इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	इंदौर-मनमाड नई लाइन (360 किलोमीटर)	18,529
2.	रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन (277 किलोमीटर)	5073
3.	इंदौर-बुदनी नई लाइन (198 किलोमीटर)	7474
4.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो नई लाइन (541 किलोमीटर)	8914
5.	नीमच-बड़ी सादड़ी नई लाइन (48 किलोमीटर)	495

6.	कोटा तक विस्तार के साथ ग्वालियर-श्योपुरकलां आमान परिवर्तन (284 किलोमीटर)	2913
7.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन (280 किलोमीटर)	2450
8.	झांसी-बीना तीसरी लाइन (153 किलोमीटर)	2002
9.	मथुरा-ग्वालियर-झांसी तीसरी लाइन (274 किलोमीटर)	5924
10.	कटनी-बीना तीसरी लाइन (260 किलोमीटर)	3138
11.	कटनी-ग्रेड सेपरेटर/बाईपास (35 किलोमीटर)	2300
12.	कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण (257 किलोमीटर)	4377
13.	सतना-रीवा दोहरीकरण (50 किलोमीटर)	590
14.	शहडोल-सिंहपुर चौथी लाइन (6 किलोमीटर)	54
15.	भुसावल-खण्डवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किलोमीटर)	3285

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 में और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, मध्य प्रदेश राज्य में 5,901 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करने वाले 61 सर्वेक्षण (18 नई लाइन और 43 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

किसी भी रेल परियोजना की मंजूरी कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार

- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****